Vastu Guruji
वास्तु हेतु संपर्क करें...
मो.नं. 9074110000
9770888888

दैनिक
सकार भारत
रायपुर-आरएनआई रजि. CHHBIL/2023/88684

वर्ष : 3 अंक : 193 पृष्ठ : 8 मुल्यः 1:00 रायपुर, शुक्रवार 24 जुलाई, 2026 www.sakarbharat.com

पेपर लीक पर मोदी बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे : युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है।

वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च

प्राथमिकता है।

पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट

देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके।

भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, रेप और **POCSO** मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है।

इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए, लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि, नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

पीएम ने कहा था- हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

परिवार में वैध जाति प्रमाण पत्र हो तो 1950 के दस्तावेज जरूरी नहीं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी परिवार के सदस्य के पास पहले से वैध जाति प्रमाण पत्र है, तो उसी परिवार के अन्य पात्र बच्चों को केवल वर्ष 1950 के दस्तावेज नहीं होने के आधार पर प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस ए.के. प्रसाद ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. प्राची दीवान ने अदालत को बताया कि प्रदेश में अनेक भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास वर्ष 1950 के राजस्व या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण उनके बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रवेश और रोजगार के लिए आवश्यक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार के किसी सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से जारी है और ग्राम सभा

या ग्राम स्तरीय समिति यह प्रमाणित करती है कि आवेदक उसी परिवार और उसी जाति से संबंधित है, तो अधिकारियों को उसके आवेदन पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों में आवेदक को अनावश्यक रूप से वर्ष 1950 के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी कर समयबद्ध तरीके से निर्णय लें। अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर पात्र आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

गजरथ यात्रा-2026 शुरू, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान तेज

रायपुर। जशपुर वनमण्डल की गजरथ यात्रा-2026 शुरू, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान तेजमानव-हाथी द्वंद की घटनाओं में कमी लाने और आमजन, विशेषकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में हाथियों के प्रति वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जशपुर वनमण्डल द्वारा गजरथ यात्रा-2026 का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान हाथी प्रभावित

संवेदनशील (येलो ज़ोन) क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है, जहां वन विभाग की टीमें विद्यालयों और गांवों में पहुंचकर हाथियों के व्यवहार, उनके प्राकृतिक आवास तथा सुरक्षित सहअस्तित्व के संबंध में जानकारी दे रही हैं।

महतारी वंदन योजना से

माताओं और बहनों के जीवन में आया आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़-सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, सुशासन और सामाजिक सुधारों पर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि हम सभी के लिए छत्तीसगढ़ महतारी है। यह माता कौशल्या की पावन जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा रही है। उन्होंने वेदों का उल्लेख करते हुए कहा कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की लगभग 68 लाख 50 हजार विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जा रहे हैं। अब तक 29 किश्तों के माध्यम से लगभग 18 हजार 800 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जब वे गांवों का दौरा करते हैं तो माताओं और बहनों के चेहरों पर इस योजना से आया आत्मविश्वास और संतोष स्पष्ट दिखाई देता है। बातचीत के दौरान माताएं और बहनें बताती हैं कि किसी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है, किसी ने सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार शुरू किया है तो किसी ने किराना या सब्जी की दुकान खोलकर आय बढ़ाई है। इससे माताएं और बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव की माताओं और बहनों ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि को एकत्र कर भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह इस योजना का सबसे प्रेरक उदाहरण है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कर रही हैं।

धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण समाज के लिए गंभीर चुनौती है। विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 लागू किया गया है। इसके तहत धर्म परिवर्तन करने और करवाने वाले दोनों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रलोभन, दबाव अथवा छलपूर्वक धर्मांतरण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

समान नागरिक संहिता की दिशा में भी तेजी से कार्य

उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र तक इस दिशा में ठोस प्रगति हो।

500 से अधिक गांवों तक पहुंची सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत अब 500 से अधिक गांवों को जोड़ा जा चुका है। लगभग 17 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का लाभ इन गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। यहां लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

30 लाख से अधिक महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख 86 हजार महिला स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें रेडी-टू-ईट कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है तथा ऋण एवं अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सिंचाई, कृषि और पर्यटन से आत्मनिर्भर बनेगा बस्तर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर देउरगांव एवं मटनार सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे लगभग 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि चित्रकोट जलप्रपात, कुटुमसर गुफाएं, अबूझमाड़ के विशाल वन तथा धुड़मारास जैसे गांव बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत पांच कमरों तक के होम-स्टे निर्माण के लिए ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, सीताफल और औषधीय वनोपजों का मूल्य संवर्धन कर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा रही है। नेतानार जैसे गांवों में सेवा डेरा के माध्यम से महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, पैकेजिंग तथा अन्य आजीविका आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

बस्तर में नक्सलवाद से विकास की ओर ऐतिहासिक परिवर्तन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चार-पांच दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और स्थानीय जनता के सहयोग से बस्तर में शांति स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैंप स्थापित करने के साथ-साथ विकास की योजनाओं को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया गया। पहले सुरक्षा शिविरों के पांच किलोमीटर दायरे तक योजनाओं का लाभ पहुंचता था, जिसे अब बढ़ाकर दस किलोमीटर तक किया गया है।

पीएससी घोटाले की जांच और रोजगार पर सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है तथा शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगी पहली राजकीय तितली

31 अगस्त तक आमजन कर सकेंगे मतदान, वनमंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों से भागीदारी की अपील की

रायपुर। छत्तीसगढ़ अपनी पहली राजकीय तितली चुनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए प्रदेशवासियों से ऑनलाइन मतदान के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। नागरिक अपनी पसंद की तितली के लिए **Google Form** के माध्यम से 31 अगस्त 2026 तक मतदान कर सकते हैं।

तीन तितली प्रजातियां दौड़ में

राजकीय तितली के चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने वैज्ञानिक और पारिस्थितिक मानकों के आधार पर तीन तितली प्रजातियों का चयन किया है। इनमें कॉमन बैंडेड पीकॉक , ऑरेंज ओकलीफ और स्पॉट स्वोर्डटेल 3 शामिल हैं। इन तितली प्रजातियों का चयन राज्य में उनकी उपलब्धता, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण मूल्य, विशिष्टता, आसानी से पहचान में आने और आमजन के आकर्षण जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया गया है।

वनमंत्री 3केदार कश्यप की पहल पर शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लेने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि जैव विविधता और वन्यजीवों का संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। जनभागीदारी से राजकीय तितली का चयन होने से लोगों में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

वन विभाग द्वारा नागरिकों की राय जानने के लिए ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद की तितली के पक्ष में मतदान कर सकता है। प्राप्त जनमत और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजकीय तितली के चयन का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, प्रकृति प्रेमियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। विभाग ने लोगों से अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण प्रतीक का चयन व्यापक जनभागीदारी से हो सके।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर किया नमन

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अदम्य साहस एवं अद्वितीय राष्ट्रभक्ति के प्रतीक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर उन्हें विनम्र नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका अदम्य साहस, अटूट आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद जी ने अपने संघर्ष, त्याग और बलिदान से देश के युवाओं में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रसेवा की अलख जगाई। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए साहस,

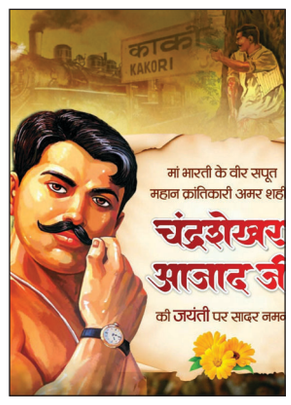

कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा का स्रोत है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदर्श और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

कलेक्टर महोबे के निर्देशन में 10 लाख 30 हजार से अधिक पौधों का होगा रोपण

जांजगीर-चांपा (वीएनएस)। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में इस मानसून 10 लाख 30 हजार 102 पौधों के वृहद वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा जलवायु संतुलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह अभियान विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के माध्यम से जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा।

इसी कड़ी में आज वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अकलतरा विकासखंड के परसाही नाला में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य बबीता रात्रे, जिला पंचायत सदस्य महादेव नेताम, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, वनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम, एसडीएम अकलतरा सुमीत बघेल, एसडीओ होरेश चन्द्र शर्मा, रेंज ऑफिसर आकाश गोस्वामी, दिक्षा पाण्डेय, आनंद मिरी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 400 से अधिक मिश्रित प्रजातियों के पौधों का रोपण कर जिले के वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया।

अभियान के अंतर्गत विभागीय पथ वृक्षारोपण योजना, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, कैम्पा (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण), किसान वृक्ष मित्र योजना, हरियाली प्रसार योजना, वन महोत्सव तथा विकसित भारत-जी राम जी अभियान के माध्यम से पौधरोपण किया जाएगा। विभागीय पथ वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत 2 किलोमीटर मार्ग पर 8 हजार पौधे लगाए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत 25 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख 38 हजार 500 पौधों का रोपण किया जाएगा। कैम्पा योजना के अंतर्गत 242.602 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 लाख 42 हजार 602 पौधे लगाए जाएंगे। किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से 70 हजार, हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत 75 हजार, वन महोत्सव के अवसर पर 1 हजार तथा विकसित भारत-जी राम जी अभियान के तहत नि:शुल्क वितरण एवं जनसहभागिता से 4 लाख 95 हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार जिले में कुल 267.602 हेक्टेयर क्षेत्र व 2 किमी सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 10,30,102 पौधों का रोपण किया जाएगा। शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों तथा उपलब्ध भूमि पर अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाएगा।

कलेक्टर महोबे ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने तथा पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधरोपण तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पौधे के संरक्षण एवं उसके विकसित होने तक नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि अभियान का वास्तविक उद्देश्य सफल हो सके।

बेटियां बनेंगी स्वावलंबी: किशोरी बालिकाओं को दिए गए आत्मरक्षा के गुर

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा के सेक्टर पहरिया के ग्राम पंचायत सत्तीगुडी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आत्मरक्षा प्रशिक्षण विषय पर किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, निडर एवं सशक्त बनाना तथा संकट की परिस्थितियों में त्वरित एवं उचित निर्णय लेने के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में बालिकाओं को आत्मरक्षा के महत्व, व्यक्तिगत सुरक्षा, सतर्कता एवं हेल्पलाइन सेवाओं के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बालिकाओं को खतरे की स्थिति की पहचान, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने तथा आवश्यकता पड़ने पर महिला हेल्पलाइन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही विद्यालय, घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर सदैव सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर बिना झिझक अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित करने की सलाह दी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण केवल शारीरिक सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम, मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता के विकास का प्रभावी साधन है। छात्राओं से नियमित अध्ययन के साथ खेल, योग एवं आत्मरक्षा गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, किशोरी बालिकाएं उपस्थित थे।

बैटरी चलित ट्रायसाइकिल बनी सोमारू नेताम की नई उड़ान

नारायणपुर । जिले के ग्राम गुडरीपारा निवासी 47 वर्षीय सोमारू नेताम का जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जब सही व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल ने उनके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव लाया है, जिसने उनकी दिनचर्या और सोच, दोनों को नई दिशा दी है।

सोमारू नेताम 75 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग हैं। लंबे समय तक दिव्यांगता के कारण उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। घर से बाहर निकलना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। बाजार जाना हो, अस्पताल पहुंचना हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना हो, हर बार उन्हें परिवार या आसपास के लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी।

महिला स्व-सहायता समूहों को मिला स्थायी रोजगार, सुगंधित विष्णुभोग चावल देशभर में बना छत्तीसगढ़ की पहचान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। भारत सरकार की एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले का पारंपरिक सुगंधित विष्णुभोग चावल आज प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। प्राकृतिक खेती, उत्कृष्ट गुणवत्ता और आकर्षक ब्रांडिंग के कारण विष्णुभोग चावल अब जीपीएम जिले की नई पहचान बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार स्थानीय कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन, आधुनिक विपणन और ब्रांडिंग से जोड़कर किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रही है। इसी सोच का

परिणाम है कि जीपीएम जिले का पारंपरिक विष्णुभोग चावल आज किसानों की समृद्धि और महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन चुका है। जिले के पेंड्रा क्षेत्र में लगभग 1,500 किसान करीब 600 एकड़ भूमि पर विष्णुभोग धान की खेती कर रहे हैं। अपनी मनमोहक सुगंध, बेहतरीन स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण यह धान उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनती जा रही है। किसानों द्वारा प्राकृतिक और पारंपरिक पद्धति से की जा रही खेती ने इसकी गुणवत्ता को और अधिक विशिष्ट बनाया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को भी उत्पादन और विपणन की मुख्यधारा से जोड़ रही है। इसी क्रम में मलनिया महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पेंड्रा किसानों से विष्णुभोग धान की खरीदी कर उसका प्रसंस्करण मिनी राइस मिल में कर रही है। आधुनिक पैकेजिंग और आकर्षक ब्रांडिंग के माध्यम से तैयार चावल को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस पहल से समूह की 15 महिलाओं को स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और लखपति दीदी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब तक समूह द्वारा लगभग 2 टन विष्णुभोग चावल की सफल बिक्री की जा चुकी है, जिससे करीब एक लाख रुपये का लाभ अर्जित हुआ है। लगातार बढ़ती मांग ने महिलाओं के आत्मविश्वास और उत्साह को नई ऊर्जा दी है।

विष्णुभोग चावल की बढ़ती लोकप्रियता ने जीपीएम जिले के किसानों के लिए नए बाजारों के द्वार खोल दिए हैं। जिले से बाहर प्रदेश के अन्य जिलों तथा विभिन्न राज्यों से भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि स्थानीय उत्पादों को उचित पहचान, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन का अवसर मिले, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले की विशिष्टता को देश-दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि स्थानीय उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो और महिलाओं को स्वावलंबन के नए अवसर मिलें।

सीईओ विनय ने परसाही नाला व अमलीपाली में निर्माणाधीन आवासों, सेग्रीगेशन शेड का किया निरीक्षण

जांजगीर-चांपा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विनय कुमार पोयाम ने जनपद पंचायत अकलतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाही नाला एवं अमलीपाली में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा कर आवास निर्माण की स्थिति, गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान एवं योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान सीईओ पोयाम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को 90 दिवस की अकुशल श्रमिक मजदूरी का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाया जाए तथा निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केवल आवास निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन का आधार है। इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। प्रत्येक निर्माण स्थल का नियमित निरीक्षण कर लंबित एवं धीमी प्रगति वाले आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए, हितग्राहियों से नियमित संपर्क बनाए रखते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए तथा निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

पीएम श्री नवोदय विद्यालय ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रसारित खबरों के संबंध में दी तथ्यात्मक जानकारी

बीजापुर ग। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बीजापुर ने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर विद्यालय के संबंध में प्रसारित की जा रही भ्रामक एवं असत्य खबरों का आधिकारिक रूप से खंडन किया है। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 20 एवं 21 जुलाई 2026 को विभिन्न समाचार माध्यमों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित समाचार तथ्यहीन, भ्रामक तथा वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत हैं। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि उक्त समाचारों का वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है तथा इनकी किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे निराधार समाचारों से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बीजापुर में कक्षा 12वीं की विज्ञान एवं गणित संकाय की बोर्ड कक्षाओं की शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित हो रही है। वाणिज्य संकाय में केवल अर्थशास्त्र विषय के एक शिक्षक की नियुक्ति शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं का संचालन नियमित एवं व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक समाचार पर विश्वास न करें तथा केवल अधिकृत एवं आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही सही मानें।

बालोद जिले में असर दिखा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

बालोद (वीएनएस)। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बालोद जिले के आम नागरिकों के जीवन में उजियारा फैलाने के साथ-साथ आर्थिक बचत का बड़ा माध्यम बन रही है। योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाते हुए जिले के गुरूर निवासी आशुतोष पंचागम ने अपने घर की छत पर 03 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित कराया है, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं।

आशुतोष के घर पिछले 07 महीनों से यह सोलर पैनल सफलतापूर्वक कार्यरत है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि शुरुआती महीनों में उनका बिजली बिल बिल्कुल शून्य (जीरो) आया। वहीं, भीषण गर्मी के दिनों में जब एसी, पंखे और कूलर का अत्यधिक उपयोग होता था, तब आमतौर पर उनका बिजली बिल 8 से 10 हजार रुपये तक पहुंच जाता था। लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद इस भीषण गर्मी के मौसम में भी उनका बिजली बिल भारी कटौती के साथ महज 1200 से 1500 रुपये ही आया। योजना की सरलता की तारीफ करते हुए आशुतोष ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी है। आवेदन के बाद वेंडर द्वारा घर का भौतिक निरीक्षण किया गया और लोन व सब्सिडी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई। जिसके बाद बेहद कम समय में उनके घर पर पैनल स्थापित कर दिए गए। उन्हें इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 01 लाख 08 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। बिजली बिल में इतनी बड़ी राहत और सरकार से मिली आर्थिक सहायता से उनका परिवार बेहद खुश है। योजना से मिली सहूलियत और बचत से उत्साहित होकर आशुतोष पंचागम ने जिले के अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि वे आगे आएं और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह योजना न केवल बिजली बिल का आर्थिक दबाव कम करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बेहतरीन कदम है।

आपदा से पहले तैयारी : बीजापुर के आत्मानंद स्कूल में बच्चों को एनडीआरएफ ने सिखाए आपदा से बचाव के व्यवहारिक गुर

बीजापुर । आपदा के समय घबराने के बजाय सही निर्णय लेकर स्वयं तथा दूसरों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से 03वीं वाहिनी एनडीआरएफ, मुंडली (ओडिशा) द्वारा फेमेक्स-2026 प्रशिक्षण अभियान के तहत जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में आपदा प्रबंधन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत 20 जुलाई को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, बीजापुर से हुई, जहां विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं आमजन को विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से बचाव के उपायों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। एनडीआरएफ के प्रशिक्षकों ने घरेलू संसाधनों का उपयोग कर आपदा की स्थिति में प्राथमिक बचाव एवं राहत कार्य करने के व्यावहारिक तरीके भी प्रदर्शित किए।

प्रशिक्षण के दौरान भूकंप की स्थिति में भवन के भीतर रहने पर मजबूत मेज या डेस्क के नीचे बैठकर सिर एवं गर्दन को सुरक्षित रखने, खिड़कियों, कांच एवं भारी वस्तुओं से दूर रहने तथा झटके रुकने के बाद शांतिपूर्वक खुले स्थान पर जाने की सलाह दी गई। वहीं यदि व्यक्ति खुले स्थान पर हो तो भवनों, बिजली के खंभों एवं पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा गया।

आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने, अग्निशमन विभाग को सूचना देने तथा छोटे स्तर की

आग को उपलब्ध अग्निशामक यंत्र, रेत अथवा अन्य सुरक्षित साधनों से नियंत्रित करने की जानकारी दी गई। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में गैस रेगुलेटर बंद करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा गीले कपड़े अथवा अग्निशामक यंत्र का सावधानीपूर्वक उपयोग करने का प्रदर्शन भी किया गया।

सांप के काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के बजाय पीड़ित को शांत रखने, प्रभावित अंग को कम से कम हिलाने तथा बिना देरी किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की सलाह दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि समय पर चिकित्सकीय उपचार ही सबसे प्रभावी उपाय है।

आकाशीय बिजली (वज्रपात) के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों एवं जलाशयों से दूर रहने, मोबाइल एवं विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग न करने तथा सुरक्षित भवन में शरण लेने के बारे में बताया गया। बाढ़ एवं पानी में डूबने जैसी परिस्थितियों में तेज बहाव वाले पानी को पार करने का प्रयास नहीं करने, सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर जाने, बच्चों पर विशेष निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर रस्सी, लाइफ जैकेट अथवा स्थानीय उपलब्ध सुरक्षित साधनों का उपयोग करने की जानकारी दी गई। साथ ही किसी व्यक्ति के डूबने की स्थिति में बिना प्रशिक्षण के सीधे पानी में छलांग न लगाने तथा तत्काल बचाव दल एवं प्रशासन को सूचना देने पर जोर दिया गया।

एनडीआरएफ के प्रशिक्षकों ने बताया कि किसी भी आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण है घबराने के बजाय सतर्क रहना, सही जानकारी का पालन करना और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर विभिन्न बचाव तकनीकों का अभ्यास किया तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की।इस दौरान एनडीआरएफ के अधिकारी एवं प्रशिक्षक सहित जिला सेनानी पीबी सिदार ,नायब तहसीलदार रविन्द्र सिन्हा सीएमओ बीजापुर बंशीलाल नुरुटी सहित जनप्रतिनिधि गण एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

महतारी वंदन योजना से बदली शकुंतला महंत की जिंदगी, मनिहारी स्टोर से बनीं आत्मनिर्भर

जांजगीर-चांपा। महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का सही उपयोग कर कई महिलाएं अपने छोटे-छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी एकीकृत बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह के सेक्टर चाम्पा ग्रामीण अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र गुरूनानक-02 की निवासी शकुंतला महंत की है, जिन्होंने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का निवेश अपने मनिहारी स्टोर में कर आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है।

शकुंतला महंत पहले अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए एक छोटा मनिहारी स्टोर चलाती थीं। इससे उनकी आमदनी भी सीमित थी और परिवार की जरूरतें पूरी करना चुनौती बना रहता था। महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि को उन्होंने खर्च करने के बजाय अपने व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लिया। हर माह मिलने वाली राशि से उन्होंने धीरे-धीरे दुकान में नए सामान जोड़ना शुरू किया। इस राशि का सदुपयोग करने से उनका कारोबार बढ़ा और ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। आज उनका मनिहारी स्टोर परिवार की आय का मजबूत आधार बन चुका है। बढ़ी हुई आय से वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर रही हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।

कभी नक्सलवाद का गढ़ रहा पीड़िया अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा

बीजापुर। जिले की गंगालूर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पीड़िया, जिसे कभी नक्सलवाद का गढ़ व नक्सलवाद की यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। वर्षों तक सुरक्षा कारणों से शासन-प्रशासन की पहुंच से दूर रहा यह गांव अब धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। 31 मार्च 2026 के बाद परिस्थितियों में आए सकारात्मक बदलाव तथा आवागमन के लिए कच्चे मार्ग बनने से प्रशासन की नियमित पहुंच संभव हो सकी है।

इसी क्रम में ग्रामीणों को शासन की मूलभूत सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत पीड़िया में विशेष आधार नामांकन एवं अद्यतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन तहसीलदार गंगालूर भोजराम डहरिया एवं नायब तहसीलदार बीजापुर रवेन्द्र सिन्हा के मार्गदर्शन में किया गया।

दूरस्थ एवं नेटवर्क विहीन क्षेत्र होने के बावजूद ग्रामीणों में शिविर को लेकर उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं बच्चे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद 80 ग्रामीणों का आधार पंजीयन एवं आवश्यक अद्यतन कार्य सफलतापूर्वक किया गया,

जिससे वे भविष्य में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक समय ऐसा था जब यह गांव नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था और कई बड़े नक्सली नेता यहां प्रशिक्षण के लिए आया करते थे। लेकिन आज वही गांव हिंसा के दौर से निकलकर शिक्षा, पहचान और विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे सामान्य एवं शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलने लगा है।

परिवर्तन की सबसे प्रेरक तस्वीर गांव का विद्यालय है, जो लगभग 21 वर्षों तक बंद रहने के बाद पुन: संचालित हो चुका है। वर्तमान में यहां 84 बच्चे नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह केवल विद्यालय का पुन: खुलना नहीं, बल्कि पीड़िया के भविष्य में लौटते विश्वास और नई पीढ़ी के बेहतर कल का प्रतीक है।

ग्राम पीड़िया में आयोजित यह आधार शिविर केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस बात का सशक्त उदाहरण है कि शासन की सेवाएं अब उन अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं, जो लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे। पहचान से अधिकार और अधिकार से विकास की यह यात्रा आज पीड़िया जैसे गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ : महिलाओं और बच्चों को साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी

बीजापुर। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत गृह विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से हेलीपेड बीजापुर तथा मोदकपाल हाट बाजार में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 डीआरजी के जवान, 100 महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में टिप्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी विषय पर साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपायों, ऑनलाइन ठगी एवं साइबर अपराधों से बचने के तरीके तथा किसी साइबर अपराध की घटना होने पर होने वाली हानि को कम करने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम, महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी साझा की गई। प्रतिभागियों को साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने और सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस विभाग से एएसआई मंजू देवांगन, एसआई पूनम शर्मा, बस्तर फाइटर भारती देवांगन, एसीआरबी महिला आरक्षक मनीषा ध्रुव, प्रधान आरक्षक मनोज टोप्पो तथा आरक्षक संजय मानिकपुरी उपस्थित रहे। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग से शीला भारद्वाज एवं राहुल कौशल ने भी सहभागिता कर जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू

सुकमा । एकीकृत बाल विकास परियोजना सुकमा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया जिले के विभिन्न ग्रामों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए की जा रही है। इस भर्ती के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद ग्राम पेन्टाचिमली के तुमलपाड, उरसांगल 2, गोंदपल्ली के मण्डीमरका 02 व 03, कोण्डासांवली 01, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के पद ग्राम ताडमेटला 02, पेन्टाचिमली के मिचीगुडा व टेकलगुडा, तारलागुडा के कलाईगुडा केंद्रों में रिक्त हैं। इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 से 05 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से ीजजचेरू/ू.म-ईींतजप.पद पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन केवल निर्धारित ई-भर्ती आंगनबाड़ी पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु अभ्यर्थी जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय अथवा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आधुनिक पशुपालन से आत्मनिर्भर बनेंगी पशु सखियाँ: उन्नत तरीकों से बढ़ेगी किसानों की कमाई

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जिले में पशु सखियों के लिए वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण का अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में मंगलवार को कुनकुरी जनपद पंचायत परिसर में पशु सखियों के लिए एक दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आजीविका), छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला जशपुर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों के माध्यम से पशु सखियों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशुपालन की व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण का उद्देश्य पशु

सखियों को ग्राम स्तर पर दक्ष सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में तैयार करना है, ताकि वे ग्रामीण पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन की नवीन तकनीकों से जोड़ते हुए पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर बकरी पालन एवं मुर्गी पालन को ग्रामीण परिवारों के लिए आय का सशक्त और टिकाऊ माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने पशु सखियों से कहा कि वे अपने-अपने गांवों में पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उन्हें बेहतर पशुपालन के लिए प्रेरित करें। प्रशिक्षण के दौरान पशुओं के रोगों की समय पर पहचान, नियमित टीकाकरण, कृमिनाशन, संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रबंधन, हरे चारे का उत्पादन, स्वच्छ पशु आवास, नस्ल सुधार, गर्भित एवं नवजात पशुओं की देखभाल, उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा रोगों की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही पशु सखियों को पशुपालन आधारित उद्यमिता, व्यवसाय योजना तैयार करने तथा सीमित संसाधनों के साथ बकरी एवं मुर्गी पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभी पशु सखियों को वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका एवं वार्षिक पशुपालन कैलेंडर वितरित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि यह कैलेंडर पशुपालकों के लिए पूरे वर्ष किए जाने वाले आवश्यक कार्यों का व्यवहारिक मार्गदर्शक है, जिससे समय पर टीकाकरण, कृमिनाशन, आहार प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके।

ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जिले के सभी आठ विकासखंडों में चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही सीएम हेल्पलाइन 1076 : चिकपाल के मेश्राम को मिली पीएम आवास की रुकी किश्त

सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 प्रदेशवासियों के लिए प्रभावी जनसमस्या समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ अंचल तक इस व्यवस्था की पहुंच ने यह साबित कर दिया है कि अब शासन आमजन के द्वार तक पहुंच रहा है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

ऐसा ही एक उदाहरण सुकमा जिले के चिकपाल से सामने आया है। ग्राम चिकपाल निवासी मेश्राम धारावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की दूसरी किस्त का भुगतान लंबित होने संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त होते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मामले का परीक्षण किया। जांच में पाया गया कि हितग्राही का आवास निर्धारित स्तर तक पूर्ण हो चुका है तथा आवश्यक अनुमोदन के बाद दूसरी किस्त के भुगतान हेतु एफटीओ जनरेट किया गया। इसके उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि हितग्राही के बैंक खाते में सफलतापूर्वक अंतरित कर दी गई। संबंधित अधिकारी ने इसकी जानकारी हितग्राही को दी, जिसके बाद शिकायत का निराकरण कर दिया गया।

यह उदाहरण प्रमाण है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान का प्रभावी तंत्र बन चुकी है। अब प्रदेश के दूरस्थ और अंतिम छोर पर बसे नागरिक भी मात्र एक फोन कॉल के माध्यम से अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचा रहे हैं और उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो रही है।

नवीन किस्मों के फलदार पौधों के रोपण हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

जशपुरनगर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में विगत दिवस 21 जुलाई 2026 को जिला पंचायत में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक की गई। बैठक में उद्यानिकी योजनाओं कें अंतर्गत संचालित कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ उद्यानिकी कृषकों को चष्ष्ट (किसान क्रेडिट कार्ड) से जोड़ने एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से होने वाले संभावित फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक कृषकों को फसल बीमा योजना से जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में शासन की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों का रोपण किए जाने हेतु समुचित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। कृषकों को अधिक आय एवं बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के साथ-साथ नवीन एवं उन्नत किस्मों के फलदार पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जशपुर जिले की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल नवीन एवं उन्नत फलदार किस्मों को जिले में परिचित एवं प्रचलित कराने की दिशा में कार्य किया जाए, ताकि कृषकों को बेहतर उत्पादन एवं अधिक आमदनी प्राप्त हो सके।

पामेड़-रासपल्ली सड़क बनने से सुदूर ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, आवागमन और विकास को मिली नई गति

बीजापुर । उसूर विकासखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित पामेड़-रासपल्ली सड़क के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्ष 2016-17 (बैच-2) में स्वीकृत 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क का मुरुमीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे लंबे समय से आवागमन की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

पूर्व में यह मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरने वाली पगडंडी था और क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता था। पामेड़ पहुंचने के लिए ग्रामीणों को तेलंगाना के चेरला होते हुए लगभग 230 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की भारी कठिनाई होती थी। सड़क निर्माण के बाद अब ग्रामीण सीधे पामेड़-रासपल्ली मार्ग से लगभग

100 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं। सड़क बनने से आसपास की अंदरूनी बसाहटों के लोगों के दैनिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। अब ग्रामीणों को हाट-बाजार, ब्लॉक मुख्यालय, अस्पताल तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए भी आवागमन आसान और सुरक्षित हुआ है।

इस सड़क का निर्माण सुरक्षा बलों के सहयोग से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरा किया गया। निर्माण कार्य के दौरान नक्सली गतिविधियों जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

सड़क निर्माण के परिणामस्वरूप पामेड़ एवं रासपल्ली के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी गति मिली है। बिजली, पेयजल, मोबाइल टावर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। साथ ही ग्रामीण अब जिला मुख्यालय से जुड़कर विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

जिले में 2 लाख 72 हजार साजा-अर्जुना पौधों का पौधरोपण शुरू, कोसा उत्पादन से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय

जशपुरनगर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। इसके साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा है।

इसी कड़ी में जिला जशपुर के अंतर्गत विकासखण्ड फरसाबहार, दुलदुला, पत्थलगांव और कुनकुरी में वर्ष 2026-27 में मनरेगा की विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्य शुरू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 19 स्थलों पर 66.5 हेक्टेयर भूमि में साजा और अर्जुना के पौधों का पौधरोपण स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक स्थल पर लगभग 14,350 पौधों के हिसाब से कुल '2 लाख 72 हजार 650 पौधों' की नर्सरी तैयार कर रोपण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाना है। साजा और अर्जुना के पौधे कोसा कीट पालन के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इन पौधों के बड़े होने पर आदिवासी और किसान परिवार प्राकृतिक कोसा उत्पादन से स्थायी और अच्छी आय अर्जित कर सकेंगे। मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों को इस कार्य से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रेशम विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में पौधों की देखभाल और रखरखाव किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय मजदूरों को पौधों की चौकीदारी के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।

सुकमा प्रशासन का दूरदराज के इलाकों पर जोर, कलेक्टर ने विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

सुकमा। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर अमित कुमार ने जनपद पंचायत कोंटा में मैराथन समीक्षा बैठक ली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों और मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सर्वोच्च

प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मनरेगा, धरसा विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, नियद नेल्लानार, बिहान और लखपति दीदी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा के तहत कोंटा में 17,768 सक्रिय श्रमिकों में से 14,424 श्रमिकों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जबकि 1 जुलाई 2026 से अब तक 84,689 मानव दिवस का सृजन किया गया है। वहीं ग्रामीण कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 26 ग्राम पंचायतों में 41 बड़े धरसा कार्य चिन्हांकित किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत 623 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सुकमा जिले की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया गया कि जिला राज्य में चौथे और बस्तर संभाग में दूसरे स्थान पर है।

कलेक्टर अमित कुमार ने शिनयद नेल्लानारश् पहल के तहत अंदरूनी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। योजना के अंतर्गत 6,175 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय स्वीकृत किए गए हैं तथा पुवर्ती, पोटकपल्ली, मण्डीमरका और सिलगेर जैसे क्षेत्रों में 12 सामुदायिक शौचालयों को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह बिहान योजना के माध्यम से कोंटा ब्लॉक के 74 प्रतिशत परिवारों को 1,474 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में श्लखपति दीदीश् पहल के तहत 1,229 के लक्ष्य के विरुद्ध 1,211 संभावित दीदियों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जा चुकी है। ग्राम पंचायत चिंनतलनार में स्थापित की जा रही श्दंडकारण्य फूड्सश् इमली प्रसंस्करण इकाई से 1,000 महिला हितग्राहियों को जोड़कर स्थानीय महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों, ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करें।

इंसानियत वो कमा सकती है, जो कोई अपने पूरे जीवन में नहीं कमा सकता

सिडनी के बॉन्डी बीच पर दिसंबर, 2025 में जब आतंकवादी हमला हुआ तो वहां मौजूद हैदराबाद निवासी 37 वर्षीय रहमत पाशा भागे नहीं, जबकि उनके पास वाहन था। इस हमले में 15 लोग मारे गए, जबकि 40 घायल हुए थे। पाशा न तो पुलिस अधिकारी थे और न ही पैरामेडिक। लेकिन उस दिन यह कैब ड्राइवर उम्मीद की किरण बन गया।

बाद में समाचारों में आया कि वे न केवल गोलियों से बचे, बल्कि कई गंभीर घायलों के पास पहुंचे, उन्हें एंबुलेंसों तक पहुंचाया और 18-20 लोगों की जान बचाई। पाशा ने घबराए लोगों की सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में भी मदद की। यह करते हुए उन्होंने खुद के डर को किनारे रखा और सदमे में आए लोगों की बातें भी धैर्य से सुनीं।

इस बुधवार खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन्हें स्थायी निवास की अनुमति दी है। उसके साथ पत्नी और तीन बच्चे भी अब वहां रह सकेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि उस दिन उन्होंने जो कैप पहनी थी, वह सिडनी म्यूजियम में प्रदर्शित की जाएगी। उन्हें कई बहादुरी पुरस्कारों के लिए भी नॉमिनेट किया गया है।

मेरे लिए यह महज साहसिक कहानी नहीं है। यह एक ऐसे वेल-परफॉर्मिंग लीडर की कहानी है, जिसने 'CARE' के साधारण सबक से बहुत-से लोगों को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया। मैं कहूंगा कि पाशा में वेल-परफॉर्मिंग लीडर के सभी गुण मौजूद थे। यह बात अलग है कि हालात ने उन्हें टैक्सी ड्राइवर बना दिया।

एक वेल-परफॉर्मिंग लीडर हमेशा जानता है कि अकसर लोग इसलिए विफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। याद रखिए, वे पर्यटक भागने या हमलावरों को काबू करने में सक्षम थे। लेकिन वे इसलिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें अपने और खुद को सफलतापूर्वक बचाने के बीच कुछ बाधाएं नजर आ रही थीं। पाशा ने वही बाधाएं देखीं। किसी अपेक्षा और तारीफ की चाह के बिना उन्होंने चुपचाप लोगों को बचाने में मदद की। उनका 'CARE' का सबक हमें चार बातें सिखाता है।

कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द नीड : अच्छे लीडर पहले 360 डिग्री पर हालात का विश्लेषण करते हैं और कार्रवाई से पहले समझते हैं कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। फुटबॉल खिलाड़ी मेस्सी से जुड़े आंकड़े याद करें। मैच में वह 83% समय मैदान पर चलते रहते हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी दौड़ रहे होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह गेंद को गोलपोस्ट में धकेलने से पहले विपक्षी खिलाड़ियों का 360 डिग्री पर जायजा लेते हैं।

अडाप्टेशन टु द सिचुएशन : कोई टैक्सी ड्राइवर चाहता तो किसी यात्री को घर छोड़कर अतिरिक्त पैसे कमा सकता था। लेकिन पाशा जानते थे कि उन्हें लोगों की जान बचानी है। इसलिए वे बार-बार लौटते रहे और कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अच्छे लीडर हमेशा समझते हैं कि अलग-अलग लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में अलग तरह की मदद की जरूरत होती है। इसीलिए लीडर को हर परिस्थिति के लिए अलग नजरिया चाहिए होता है। सरल शब्दों में अच्छा लीडर खुद को हालात के मुताबिक ढालता है।

रिमूव बैरियर्स : पाशा ने तत्काल हमलावरों की बाधाओं को पार किया और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अच्छे लीडर कर्मचारियों और लक्ष्यों के बीच मौजूद बाधाओं को पहचानते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं।

एनेबल सक्सेस : उस कठिन समय में पाशा ने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कई तरीके से मदद की। अच्छे लीडर हर समस्या खुद हल नहीं करते। वे रुकावटों को हटाते हैं, ताकि लोग खुद अपनी समस्या हल कर सकें।

बॉन्डी बीच जैसे हर हिंसक हमले को उसमें जान गंवाने वाले मासूम लोगों के लिए याद किया जाएगा। लेकिन ये हमले असाधारण काम करने वाले साधारण लोगों के लिए भी उतने ही याद किए जाते हैं- गोलीबारी की ओर दौड़ते पुलिस अधिकारी, अपने सर्फबोर्ड को स्ट्रेचर में बदलने वाले लाइफसेवर्स, आतंकवादी को निहत्था करने वाला कोई दुकानदार और वो भारतीय कैब ड्राइवर, जिसने टैक्सी को कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया।

फंडा यह है कि नफरत सुर्खियां बना सकती है, लेकिन अच्छे लीडर इंसानियत के जरिए ऐसी कहानियां लिखते हैं, जो लंबे समय तक याद की जाती हैं। वे अपने कर्मचारियों की परवाह करके उन्हें वर्कप्लेस पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद भी करते हैं।

कहीं 'पंजाबिस्तान' भर ना रह जाए पाकिस्तान...

करन सिंह होरा
संपादक
साकार भारत

पाकिस्तान का 44 प्रतिशत भूभाग बलूचिस्तान में आता है। इस इलाके में करीब 1.4 करोड़ की छितराई हुई आबादी बसती है, जो पाकिस्तान की कुल 25 करोड़ से अधिक आबादी का छोटा-सा ही हिस्सा है। मार्च 1948 में- जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया- तब ही से यह सूबा पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ता आ रहा है।

1947 में बंटवारे के समय बलूचिस्तान 'कलात' नाम की एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसके शासक मीर अहमद यार खान हुआ करते थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने कलात पर पाकिस्तान में विलय का दबाव डाला था। हालांकि, उसके बाद से बीते सात दशकों से बलूच नेतृत्व और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच के रिश्ते उथल-पुथल भरे ही रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बीते कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। 5 जुलाई को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के जियारत जिले में मंगी बांध की सुरक्षा कर रहे नौ पुलिसकर्मियों को मार दिया था।

8 जुलाई को बीएलए उग्रवादियों ने पाकिस्तानी सेना के वाहन पर घात लगा कर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। इसी बीच, बीएलए उग्रवादियों ने मस्तुंग जिले में भी पाकिस्तान सेना के काफिले को बम से उड़ा दिया, जिसमें अनुमानत: 45 सैनिकों की मौत हो गई। एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अपने देश का नाम 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' रख दिया है।

हालांकि, इन दावों को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि चीन और अमेरिका, दोनों की ही दिलचस्पी शांतिपूर्ण बलूचिस्तान में है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (सीपैक) बनाकर बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। वहीं, अमेरिका बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों, सोने और तांबे की खदानों तथा तेल सम्पदा तक पहुंच बनाना चाहता है।

भारत भी इस पूरे मसले पर नजर बनाए है। स्थानीय बलूच नेता मीर यार बलूच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का राष्ट्रगान जारी किया है और भारत से नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने का अनुरोध किया है। हालांकि, नई दिल्ली ने फिलहाल तो इस पर सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया ही दी है, क्योंकि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के आसपास सुरक्षा हालात अभी अस्थिर बने हुए हैं।

आज सीखने वाला हर बच्चा देश के कल को ही मजबूत बनाता है

जब हमारी सरकार ने 2021 में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की, तब हमने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे कहना तो आसान था, लेकिन हासिल करना कठिन- भारत का प्रत्येक बच्चा तीसरी कक्षा के अंत तक समझ के साथ पढ़ सके और बुनियादी गणित के प्रश्न हल कर सके। पांच वर्ष बाद उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि भारत ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक शांत लेकिन परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत कर दी है।

हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक का निर्माण किया है, जिसमें 25 करोड़ विद्यार्थी, 98 लाख शिक्षक और 15 लाख विद्यालय शामिल हैं। इसके माध्यम से लगभग हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कई वर्षों तक बड़ी संख्या में बच्चे बिना बुनियादी साक्षरता हासिल किए ही शुरुआती कक्षाओं से आगे बढ़ते रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस कमी को 'लर्निंग क्राइसिस' के रूप में चिह्नित किया और निपुण भारत मिशन इसी चुनौती के समाधान के रूप में शुरू किया गया। हमने इस संकल्प के साथ संसाधन भी जोड़े और मिशन का वार्षिक आवंटन इसकी शुरुआत के समय लगभग 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आज लगभग 4,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। देशभर में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में चुपचाप एक बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा है, जिसकी झलक राष्ट्रीय आकलनों और स्वतंत्र मूल्यांकनों- दोनों में दिखाई देती है। एनसीईआरटी के परख आकलन के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने भाषा में औसतन 64 प्रतिशत और गणित में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

इन निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए असर-2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले दो दशकों के दौरान बुनियादी शिक्षा में सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया है। कक्षा 3 के जिन बच्चों को साधारण जोड़-घटाव करना आता है, उनका अनुपात बढ़कर लगभग 34 प्रतिशत हो गया है। अब कक्षा 3 के लगभग 23.4 प्रतिशत बच्चे सहजता से कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं, जो 7.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि है।

फिर भी सबसे उत्साहजनक कहानी इन राष्ट्रीय औसतों के पीछे छिपी है। अब ग्रामीण भारत के बच्चे शुरुआती कक्षाओं में अपने शहरी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि लड़कियां तो लड़कों से आगे हैं। हम उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक वंचना का सामना करना पड़ा, विशेषकर दूरदराज और संसाधन-विहीन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक। इससे सीखने के परिणामों में लंबे समय से बनी असमानताओं को कम करने में मदद मिल रही है।

इतने व्यापक स्तर पर हुई यह प्रगति केवल संयोग भर नहीं है। इसके लिए सुनियोजित, संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। इन्होंने बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। कम लागत वाले टीचिंग-लर्निंग मटैरियल्स यानी टीएलएम के जरिये सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया गया है।

यूपी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां कक्षा 1 से 3 तक के लिए व्यापक टीएलएम व्यवस्था विकसित की गई है। इसमें प्रिंट-समृद्ध कक्षाएं, वर्कबुक्स और खेल-आधारित वंडरबॉक्स शामिल हैं। जो बच्चा शुरुआती वर्षों में पढ़ना, तर्क करना और समस्याओं का समाधान करना सीखता है, वह बड़ा होकर एक सशक्त वर्कफोर्स बनता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए बुनियादी शिक्षा विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण के केंद्र में है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चंद महीनों के युद्ध से कई देश एक दशक पीछे चले गए हैं

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के बार-बार शुरू होने, रुकने वाले युद्ध के तेल बाजारों पर असर पर विचार करें। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से वे अत्यधिक अस्थिर रहे हैं, लेकिन उनके उतार-चढ़ाव ने मांग और आपूर्ति के बजाय बदलती धारणाओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिम्बित किया है- जो अकसर ट्रम्प की सोशल मीडिया पोस्टों से आकार लेती हैं।

निश्चित रूप से, ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने से वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा आई। लेकिन शिपिंग की दूरी और परिवहन में देरी का मतलब था इसका प्रभाव उपभोक्ताओं और उत्पादकों को तुरंत महसूस नहीं हुआ। फिर भी, विरोधाभासी आधिकारिक घोषणाओं के बार-बार बाजार की उम्मीदों को बदलने के कारण तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव हुआ।

जुलाई की शुरुआत तक, अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्धविराम समझौते के बाद, क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था- जो लगभग उस स्तर पर था, जहां यह युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी में था। लड़ाई फिर से शुरू होने पर भी अब तक कीमतों में केवल मामूली वृद्धि ही हुई है। वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद, अमेरिकी शेयर बाजारों ने अप्रैल और जून के बीच 2020 के बाद से अपनी सबसे अच्छी तिमाही दर्ज की और जुलाई की शुरुआत में बढ़ना जारी रखा। इस तेजी का नेतृत्व एआई शेयरों ने किया, जिसे इस विश्वास से बल मिला कि एआई उत्पादकता और आर्थिक विकास में अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगा। कुछ हद तक, यह समृद्ध देशों में आर्थिक गतिविधि पर युद्ध के अपेक्षाकृत सीमित प्रभाव को दर्शाता है।

आईएमएफ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि में मामूली मंदी का अनुमान लगाता है, जो 1.7% है। वहीं अमेरिका के 2.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में, बेरोजगारी दर अप्रैल में 5% थी, जो फरवरी 2022 से लगभग अपरिवर्तित है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के इस लचीलेपन का श्रेय काफी हद तक एआई और क्रिप्टोकरेंसी निवेश में हालिया उछाल को दिया जा सकता है।

कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं- विशेष रूप से चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया को भी इससे लाभ हुआ है। वित्तीय बाजारों की वर्तमान आत्मसंतुष्टि इस व्यापक धारणा से और मजबूत हुई है कि दोनों पक्षों की आक्रामकता के बावजूद ईरान के साथ युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, या यह केवल एक कम-तीव्रता वाले संघर्ष के रूप में जारी रहेगा, जो होर्मुज से आंशिक आवागमन की अनुमति देता है।

फिर भी यह आत्मविश्वास युद्ध के दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों को अनदेखा करता है। युद्धविराम के बावजूद, खाड़ी से तेल का निर्यात युद्ध-पूर्व स्तर से काफी नीचे रहा। और भले ही निर्यात पूरी तरह से ठीक हो जाए, निम्न-आय वाले देश आने वाले वर्षों तक आज के ऊर्जा-संकट की लागत वहन करते रहेंगे। सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उप-उत्पादों में उर्वरक शामिल हैं, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि 2026 की पहली छमाही में वैश्विक उर्वरक की कीमतों में 15-20% की वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, किसानों को- विशेषकर निम्न-आय वाले देशों में उर्वरक की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ सिंचाई और परिवहन के लिए ईंधन की उच्च लागत से भी जूझना होगा।

खाद के उपयोग में मामूली कमी भी फसल उत्पादन में भारी गिरावट ला सकती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चीन और भारत को छोड़कर, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर महामारी से पहले के स्तर पर 2028 के बाद तक वापस नहीं आएगा।

विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर महामारी से पहले के स्तर पर 2028 के बाद तक वापस नहीं आएगा। ग्लोबल साउथ के कई देशों ने युद्ध से एक पूरा दशक गंवा दिया है।

(@ प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

युग तुलसी श्रीरामकिंकर उवाच ...

मंथरा महान कूटनीतिज्ञ थी, तथा मानव मन की दुर्बलताओं को जानने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। यह मंथरा नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने की सबसे बड़ी योग्यता का प्रमाण है कि उसे बहुत कथाएं याद थीं। यहां तक कि जब कैकेई से वार्तालाप हुआ तो वह उन्हें पुराणों की कथा कहने-सुनाने लगी। और जब मंथरा से समस्त कथाएं उन्होंने सुनीं तो कैकेईजी मुंह ताकने लगीं कि जितनी कथाएं मुझे याद नहीं है उतनी तुम्हें याद है। लेकिन उसने केवल वही कथाएं याद रखी थीं जिनमें

सौतों से झगड़ा हुआ हो। मंथरा ने सारी कथाओं में यही दोहराया कि - कहसि कथा सत सबति कै - किस सौत ने अपनी किस सौत को दुख दिया है। इसी प्रकार कौशल्या भी तुमको दुख देने वाली है। उसकी कथा का सार यह है कि तुम सौत से बदला लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार यह मंथरा बड़ी तीव्र बुद्धि वाली है।

शिष्य विशु व्ही.पी. नेगी
श्री रामकिंकर आध्यात्मिक मिशन रायपुर
मो.नं. 9425227937

साजिश के सिद्धांतों को कभी सच्चाई पर हावी ना होने दें

दिल्ली के सत्ता गलियारों में साजिश के सिद्धांत (कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़) हमेशा फलते-फूलते रहे हैं। लेकिन आज के अत्यधिक ध्रुवीकृत भारत में वे केवल गपशप भर नहीं रह गए हैं। अब वे राजनीतिक हथियार बन चुके हैं, जिनका इस्तेमाल विरोधियों की वैधता पर सवाल उठाने, आंदोलनों को बदनाम करने और असहज सवालों का सामना करने से बचने के लिए किया जाता है।

ताजा निशाने पर हैं सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), जो राष्ट्रीय राजधानी को झकझोर देने वाले छात्र आंदोलनों की पृष्ठभूमि में हैं। यह पूछने के बजाय कि पेपर लीक, परीक्षाओं में देरी और बेरोजगारी को लेकर युवा क्यों नाराज हैं, उन लोगों की मंशा पर सवाल उठाने में अधिक रुचि दिखाई जा रही है, जो इन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं।

कांग्रेस से जुड़े समूहों में व्यापक रूप से प्रचलित एक सिद्धांत के अनुसार, वांगचुक और सीजेपी सरकार के ही 'डीप स्टेट' का हिस्सा हैं, जिन्हें इसलिए आगे किया गया, ताकि नीट विवाद को उठाने का राजनीतिक श्रेय कांग्रेस को न मिल सके। इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। फिर भी ऐसे दौर में, जब संदेह तथ्यों से अधिक तेजी से फैलता है, साजिश के सिद्धांत भी बहुत जल्दी अपनी पैठ बना लेते हैं।

सोनम वांगचुक का मामला ही देखिए। जब लद्दाख में अधिक स्वायत्तता की मांग वाला आंदोलन तेज हुआ, तब वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने छह महीने जेल में बिताए और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें क्यों कैद किया गया था, इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उन्हें विदेशी फंडिंग से जुड़ा, राष्ट्र विरोधी और चीन-समर्थक एजेंट तक बताया गया। उनके भाषणों के चुनिंदा हिस्सों को संदर्भ से अलग करके एक सुविधाजनक नैरेटिव के अनुरूप प्रस्तुत किया गया।

अब विडम्बना यह है कि उसी व्यक्ति को कुछ नेता आईबी की कठपुतली बता रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियान से ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ाया गया है। कोई व्यक्ति पहले चीन-समर्थक बताकर बदनाम किया जाए और फिर उसी पर भारतीय-सत्तातंत्र के लिए काम करने का आरोप लगाया जाए- ऐसा कैसे हो सकता है?

मैं सोनम वांगचुक को लगभग दो दशकों से जानता हूं। उनसे मेरी पहली मुलाकात 2008 में हुई थी, जब शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए उन्हें रियल हीरो सम्मान से नवाजा गया था। कोई व्यक्ति उनके हर विचार से सहमत हो या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद ही इस स्वीकार्यता पर टिकी है कि सत्ता से असहमति का अर्थ देश से विश्वासघात नहीं होता।

स्वयं केंद्र सरकार ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से वांगचुक के कार्य की सराहना की है। मार्च 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वांगचुक और उनकी पत्नी से मुलाकात के बाद एक्स पर एक तस्वीर साझा की थी और शिक्षा-प्रणाली को बदलने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की थी। अब जब वांगचुक नीट विवाद में जवाबदेही की मांग उठाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए हैं, तब वह प्रशंसा गायब हो चुकी है।

दूसरी ओर, सीजेपी को भी सरकार इंटरनेट तक सीमित एक मामूली समूह मानकर नजरअंदाज करती रही थी। लेकिन जब छात्र सड़कों पर उतर आए, तब जाकर उसके अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू किया। कांग्रेस ने भी मान लिया था कि सीजेपी दरअसल आप पार्टी का ही मुखौटा है, क्योंकि उसके संस्थापक का कभी आप पार्टी से संबंध रहा था। शायद कांग्रेस आज भी 2011 के जख्मों को याद रखे हुए है, जब अण्णा हजारे का आंदोलन उसकी सरकार के पतन की प्रक्रिया को तेज कर गया था।

कांग्रेस से जुड़े समूहों में व्यापक रूप से प्रचलित एक सिद्धांत के अनुसार, वांगचुक और सीजेपी सरकार के ही 'डीप स्टेट' का हिस्सा हैं, जिन्हें इसलिए आगे किया गया, ताकि नीट विवाद को उठाने का श्रेय कांग्रेस को न मिल सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

26 जुलाई को प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा:रायपुर के 52 केंद्रों में होगी परीक्षा,16,987 अभ्यर्थी होंगे शामिल ,तैयारियां पूरी, फ्रिस्किंग होगी अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 26 जुलाई रविवार को रायपुर जिले के 52 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। परीक्षा में 16,987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी और विशेष रोजगार कार्यालय के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री का वितरण 26 जुलाई की सुबह 6 बजे जिला कोषालय से किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों का सख्ती से होगा पालन

बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया।

अपर कलेक्टर ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग की जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और सभी तैयारियां समय पर पूरी कर परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए।

किराए पर उपलब्ध है

तेलीबांधा शीतल कॉम्प्लेक्स में दुकान/ऑफिस के लिए जगह किराए पर उपलब्ध है।

संपर्क-9302222222

रायपुर में संपत्ति कर जमा करने पर अब 5% छूट, 30 सितंबर तक मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान पर छूट की घोषणा की है। अब 30 सितंबर 2026 तक पूरा संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम ने पहले संपत्ति कर भुगतान पर 6.25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा था, लेकिन अब इसे संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले लोगों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। नगर निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, यह छूट केवल निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान करने वालों के लिए लागू होगी। जो करदाता 30 सितंबर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा संपत्ति कर जमा कर देंगे, उन्हें ही 5 प्रतिशत की राहत मिलेगी। समय सीमा खत्म होने के बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत ही संपत्ति कर जमा करना होगा और छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई नीति लागू:11 माह सेवा और 2000 प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान

पीरियड आधारित व्यवस्था खत्म, 11 वैतनिक अवकाश भी मिलेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत पीरियड आधारित व्यवस्था समाप्त कर ?2000 प्रतिदिन मानदेय, 11 माह की सेवा और 11 वैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।

नई व्यवस्था से उन महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को विशेष लाभ मिलने की संभावना है, जहां अब तक उन्हें प्रतिमाह लगभग ?20 हजार से ?25 हजार तक मानदेय मिलता था। नई नीति लागू होने के बाद उनका मासिक मानदेय बढ़कर लगभग ?40 हजार से ?42 हजार तक पहुंच सकता है।

नई नीति में सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। पहले कई महाविद्यालयों में दिसंबर और जनवरी के सेमेस्टर परीक्षा अवधि के दौरान अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं समाप्त कर दी जाती थीं, जिससे उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता था।

अब 11 माह की सेवा मिलने से इस समस्या के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधित व्यवस्था के तहत अतिथि व्याख्याताओं की श्रेणी दैनिक वेतनभोगी के रूप में भी निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा है कि नीति के क्रियान्वयन के दौरान यदि किसी प्रकार की व्यावहारिक समस्या सामने आती है तो विभाग स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा।

नई नीति लागू होने के बाद प्रदेशभर के अतिथि व्याख्याताओं ने इसका स्वागत किया है। शासकीय मूल निवास अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लव कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव डॉ. कमलेश देशमुख, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष आलोक चतुर्वेदी सहित पदाधिकारियों ने इसे आर्थिक सुरक्षा और सेवा की स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

23-24 जुलाई को रद्द की गई 4 मेमू ट्रेन बहाल:

चार ट्रेनें अब भी रद्द रहेंगी, भाटापारा-हथबंध में ऑटो सिग्नलिंग काम होगा

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भाटापारा-हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। रेलवे ने पहले जिन ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की थी।

इनमें से चार मेमू ट्रेनों को बहाल (रिस्टोर) कर दिया है। ये ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय पर चलेंगी।

ये 4 ट्रेनें अब रद्द नहीं होंगी

रेलवे के संशोधित आदेश के अनुसार 23 जुलाई को चलने वाली ये ट्रेनें अब सामान्य रूप से संचालित होंगी।

68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू

68734 बिलासपुर-कोरबा मेमू

68733 कोरबा-बिलासपुर मेमू

68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू

अब ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

संशोधित सूची के अनुसार अब भी ये ट्रेनें रद्द रहेंगी।

23 जुलाई: 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर

23 जुलाई: 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर

23 जुलाई: 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू

24 जुलाई: 68745 कोरबा-रायपुर मेमू

इस ट्रेन का आंशिक परिचालन

23 जुलाई को चलने वाली 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू केवल बिलासपुर तक ही चलेगी। यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त और वहीं से प्रारंभ होगी। बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा।

क्यों किया गया बदलाव?

रेलवे के अनुसार रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग की कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं।

रायपुर में 26 जुलाई को भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह

रायपुर। रायपुर में 26 जुलाई को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई की ओर से भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम की शुरुआत 25 जुलाई को शाम 4:30 बजे आकाशवाणी चौक में वीर चक्र से सम्मानित शहीद कौशल यादव की श्रद्धांजलि सभा से होगी। इसके बाद आकाशवाणी चौक से कलेक्ट्रेट चौक, मोती बाग, कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक, संतोषी नगर और बोरिया खुर्द होते हुए मां दुर्गा मंदिर परिसर, कांदुल तक भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी।

वीर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

26 जुलाई को मां दुर्गा मंदिर परिसर, कांदुल स्थित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद परिवारों और कारगिल योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कविता पाठ भी होगा।

आयकर रिटर्न में बड़ा बदलाव:शादी के गिफ्ट से सोलर सब्सिडी तक बतानी होगी, ब्योरा छिपाया तो जुर्माना

रायपुर। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस बार करदाताओं को अधिक सावधानी बरतनी होगी। नियमों में बदलाव के बाद पहली बार शादी-समारोह या रिश्तेदारों से मिले उपहार की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और सरकारी योजनाओं के तहत मिली सब्सिडी या अनुदान का ब्योरा भी आईटीआर में दर्ज करना होगा। जानकारी छिपाने पर जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल तक हो सकती है। अब वसीयत या संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे से मिली संपत्ति, कृषि भूमि की बिक्री और महतारी वंदन जैसी सरकारी योजनाओं से मिली राशि की जानकारी भी देनी होगी। सोलर सब्सिडी समेत दूसरी सरकारी सहायता भी इसके दायरे में आएगी। इन पर मिलने वाली आयकर छूट पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन आईटीआर में इनका उल्लेख अनिवार्य होगा। पहले ऐसी करमुक्त प्राप्तियों की विस्तृत जानकारी देना जरूरी नहीं था।

वरिष्ठ सीए एवं टैक्स बार ट्रिब्यूनल के चेतन तारवानी ने बताया कि करदाताओं को आईटीआर भरने से पहले अपना बैंक स्टेटमेंट जांचना चाहिए। खाते में किसी सरकारी योजना, सब्सिडी या अनुदान की राशि जमा हुई है तो उसे रिटर्न में दिखाना होगा। नए प्रावधान से करदाताओं को राहत भी मिलेगी। अब तक ऐसी करमुक्त प्राप्तियों की जानकारी सरकार को देने के लिए रिटर्न में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। नए प्रारूप में इन्हें दर्ज किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ में करीब 16 लाख लोग, संस्थाए और कंपनियां इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। सीए एसोसिएशन के अनुसार अभी 65 प्रतिशत ने रिटर्न दाखिल कर दिया है। 31 जुलाई तक यह संख्या 90 से 95 फीसदी के आसपास जाने की संभावना है।

बाकी लोग तकनीकी और कई कारणों से रिटर्न जमा नहीं करते हैं। हालांकि इनमें भी बाद में लोग 1000 रुपए जुर्माना शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर देते हैं। एसोसिएशन के अनुसार अभी 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने वालों में सबसे बड़ी संख्या नौकरीपेशा वालों की है।

रायपुर में सड़क किनारे ट्रक पार्क करने वालों की खैर नहीं, 3 चालकों पर केश दर्ज

रायपुर। रायपुर में सड़क किनारे अवैध रूप से ट्रक और ट्रेलर खड़े करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 'पत्रिका' में 'मौत को दावत देते हुए सड़कों पर खड़े ट्रक' शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और रिंग रोड पर विशेष अभियान चलाकर कई भारी वाहनों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान तीन वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात थाना टाटीबंध और थाना आमनाका की संयुक्त टीम ने हीरापुर मार्ग, बिलासपुर रोड और टाटीबंध चौक के आसपास सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रक एवं ट्रेलरों के खिलाफ अभियान चलाया।

अभियान के दौरान सड़क पर यातायात बाधित करने वाले और नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान किए गए। वहीं, तीन भारी वाहन चालकों को थाना आमनाका भेजा गया, जहां उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

रिंग रोड पर बढ़ रहा था हादसों का खतरा

सड़क किनारे लंबे समय तक खड़े रहने वाले भारी वाहनों के कारण रिंग रोड पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था। इससे आम वाहन चालकों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल अभियान चलाकर स्थिति सुधारने की कार्रवाई की।

वाहन चालकों को दी गई समझाइश

कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस ने ट्रक और ट्रेलर चालकों को सड़क पर अनधिकृत पार्किंग नहीं करने और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की सलाह दी। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि राजधानी में यातायात सुरक्षित और सुचारु बना रहे।

यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क किनारे भारी वाहनों की अवैध पार्किंग से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और यातायात भी प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया।

रायपुर में छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की शूटिंग प्रतियोगिता:शिवम ने जीता गोल्ड मेडल, निशानेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई नेशनल के लिए चयनित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की ओर से 12 से 21 जुलाई तक आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्य के डीजी और अन्य वरिष्ठ अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमे से कई खिलाड़ी अब नेशनल लेवल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। राज्य के विभिन्न जिलों से अनेक युवा एवं बच्चों ने भाग लिया। रायपुर की टॉपगन शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शिवम गुप्ता ने 391 अंक के साथ सीनियर वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। नमन साहू ने यूथ और जूनियर वर्ग में रजत, आध्या सिंह ने जूनियर और सीनियर वर्ग में रजत, जबकि नायरा मदनानी ने जूनियर और सीनियर वर्ग में चार रजत पदक अपने नाम किए। लक्ष्य, धैर्य अंबानी, रागिनी शर्मा, वान्या त्रिपाठी, अभिनव सिंह, इशान साहू और रवीश झा समेत कई खिलाड़ियों ने भी विभिन्न वर्गों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए।

इसके अलावा 25 मीटर स्पर्धा में वैष्णव त्रिपाठी ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लिपिका ठाकुर, प्रतीक्षा ठाकुर, आदित्य शर्मा, तुलजा भवानी और आरवी दुबे ने भी अपने-अपने वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। प्रतियोगिता के नतीजों के आधार पर कई खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अकादमी के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 45 से ज्यादा पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया।

खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, प्रशिक्षकों और टॉपगन शूटिंग अकादमी को दिया तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प जताया।

Vastu Guruji

BEST PLACE FOR VASTU REMEDY

BUY NOW >

CALL 9770888888

वास्तु गुरुजी सिकंदर राणा जी के अनुसार आज का राशिफल

मो.नं. : 9770888888

मेष। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं तथा पुराने ग्राहकों से लाभ होने की संभावना है। हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ और जिम्मेदारियों के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ। आज आपकी व्यावहारिक सोच और समझदारी आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ेंगे। पुराने अवसर फिर से सामने आ सकते हैं, इसलिए उन्हें पहचानकर सही समय पर निर्णय लें।

मिथुन। बुध के आपकी राशि में मार्गी होने से आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आपकी वाणी, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता लोगों को प्रभावित करेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापारियों के लिए नए अनुबंध और लाभदायक सौदे मिलने के योग हैं।

कर्क। आज मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। आर्थिक योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है और निवेश से जुड़े निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

सिंह। आज करियर में तरक्की के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व गुणों और कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है। व्यापारियों के लिए भी लाभदायक समय रहेगा तथा नई योजनाओं से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रियजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या। आज कार्यभार अपेक्षाकृत अधिक रहने के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और नियमित योग, ध्यान तथा पर्याप्त विश्राम का सहारा लें। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और अनुशासन से सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी तथा अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा।

तुला। आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि किसी प्रियजन से मतभेद चल रहे हैं तो बातचीत के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सकता है। साझेदारी के कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और व्यापार में नई संभावनाएं सामने आएंगी। यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।

वृश्चिक। चंद्रमा के आपकी राशि में गोचर करने से आज आपकी भावनाएं गहरी और संवेदनशील रहेंगी। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे और पुराने प्रयास सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

धनु। आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी तथा किसी शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा तथा जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

मकर। आज आपकी कड़ी मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी तथा पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा तथा घर का वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है।

कुंभ। आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और नई योजनाएं अधिकारियों को प्रभावित करेंगी। भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का वातावरण सुखद रहेगा तथा जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं।

मीन। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी। कला, साहित्य, संगीत या सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई और नई चीजें सीखने के लिहाज से अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके साथ रहेगी।

पलामू में मिला 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का भंडार

डीजीपीएस सर्वे और डिमार्केशन का काम पूरा, अब नीलामी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

मेदिनीनगर। सतबरवा प्रखंड में खामडीह और पूर्णाडीह के बीच 12 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट का भंडार मिला है। यह पलामू प्रमंडल में अब तक का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार है।

खनन एवं भूतत्व विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र उरांव ने बताया कि इस साल जनवरी-फरवरी में सतबरवा क्षेत्र में ड्रिलिंग के दौरान ग्रेफाइट होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद डीजीपीएस सर्वे और डिमार्केशन का काम पूरा किया गया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंप दी गई है। इस भंडार का ग्रेड 7.7 कार्बन वाला है।

ग्रेफाइट की वैश्विक मांग बढ़ने से पलामू में बंद पड़ी माइंस फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। 80 के दशक में वन अधिनियम लागू होने से चांदो सोकरा क्षेत्र की प्रसिद्ध माइंस बंद हो गई थी। डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि सोकरा माइंस चालू कराने के लिए बातचीत चल रही है। सतबरवा में नया भंडार मिलने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

अन्य प्रखंडों में भी सर्वे

खनन विभाग अब अन्य प्रखंडों में भी सर्वे कर रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि पलामू के विभिन्न इलाकों में और भी उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट भंडार मिल सकते हैं। वहीं जो भंडार मिले हैं, उसकी नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निजी कंपनियां यहां निवेश करेंगी। इससे क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। ग्रामीणों की मांग है कि खनन शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाए।

लिथियम बैटरी और परमाणु क्षेत्र के लिए संजीवनी

पलामू में मिला ग्रेफाइट लिथियम बैटरी, परमाणु उद्योग, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील के फर्नेस में भी उपयोग किया जाता है। आम तौर पर लोग ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने की सामग्री समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी मांग अब लिथियम आयन बैटरी और परमाणु रिएक्टरों में है। इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते चलन के कारण ग्रेफाइट की मांग अगले 10 सालों में कई गुना बढ़ने का अनुमान है।- संतन चक्रवर्ती जियोलॉजिस्ट

सीएम ने आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की समीक्षा की:3 साल में हर पंचायत में 5जी नेटवर्क, जिलों में होंगे आईटी अधिकारी: सीएम

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अगले तीन वर्षों में राज्य की सभी पंचायतों तक 5जी नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि 'डिजिटल झारखंड' का सपना तभी साकार होगा, जब तकनीक का लाभ दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे तथा कोई भी नागरिक डिजिटल सेवाओं से वंचित न रहे।

झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और आईटी आधारित नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डिजिटल तकनीक केवल सरकारी कामकाज को आसान बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मजबूत नींव है। उन्होंने प्रत्येक विभाग और

जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग व डिजिटल सेवाओं के संचालन में तेजी आ सके।

बैठक में 'डिजिटल झारखंड विजन-2029' के तहत आईटी पार्क निर्माण की रूपरेखा, चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तथा विभिन्न विभागों के डेटा के केंद्रीकरण पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव पूजा सिंघल, विशेष सचिव सुनील कुमार सिंह, निदेशक माधवी मिश्रा, जैप-आईटी के सीईओ चंदन कुमार आदि उपस्थित थे।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी राज्यव्यापी मैपिंग

मुख्यमंत्री ने झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए पूरे राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहले यह पता लगाया जाए कि किन क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की कमी है, फिर उसी आधार पर योजनाबद्ध तरीके से नेटवर्क का विस्तार किया जाए। उन्होंने भारतनेट फेज-3, कनेक्टिंग झारखंड और झारनेट 2.0 को राज्य के डिजिटल विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि गांव, कस्बा या शहर, कोई भी क्षेत्र डिजिटल सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क जरूरी है।

सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करने के निर्देश

जैप-आईटी की समीक्षा के दौरान सीएम ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क तथा लिडार व सैटेलाइट आधारित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी सरकारी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाएं, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके। जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाले साउंड सिस्टम लगाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास केवल आईटी पार्क तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूत आईटी इकोसिस्टम विकसित कर स्टार्टअप, नवाचार, कौशल विकास व आईटी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित हों।

धनबाद में रेल ट्रैक के पास जमीन धंसी:डीसी रेलखंड पर सुरक्षा चिंता बढ़ी, गोफ की भराई हुई; ट्रैकमैन की सतर्कता से मिली जानकारी

धनबाद। धनबाद-चंद्रपुरा रेलखंड पर सोनारडीह रेल केबिन के पास ट्रैक से महज चार मीटर की दूरी पर जमीन धंस गई, जिससे एक गोफ बन गया। बुधवार को ट्रैक पर गश्त कर रहे ट्रैकमैन की सतर्कता से इसकी जानकारी अधिकारियों को मिली, जिसके बाद रेलवे और बीसीसीएल की टीम ने तत्काल भराई का कार्य कराया।

सोनारडीह रेल केबिन के पास ड्यूटी पर तैनात ट्रैकमैन ने ट्रैक निरीक्षण के दौरान जमीन धंसने से बने गोफ को देखा। संभावित खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही रेलवे विभाग और बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बिना देर किए गोफ की भराई कराई ताकि रेल परिचालन पर किसी तरह का खतरा न बने।

प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि मिट्टी कटाव और क्षेत्र में कोयला खनन की गतिविधियां इस घटना की वजह हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

यह उल्लेखनीय है कि इसी डीसी रेलखंड के नीचे भूमिगत आग की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर 15 जून 2017 से इस रेलमार्ग को बंद कर दिया गया था। उस समय 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था।

लगभग दो वर्षों तक चले जन आंदोलन के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया गया था। अब एक बार फिर रेल ट्रैक के समीप गोफ बनने की घटना ने इस महत्वपूर्ण रेलमार्ग की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोयलांचल की लाइफलाइन माने जाने वाले धनबाद-चंद्रपुरा रेलखंड पर भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थायी समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

सरिया को जिला बनाने की मांग पर अनशन शुरू: संघर्ष मोर्चा ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

गिरिडीह। गिरिडीह के सरिया अनुमंडल को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर बुधवार से 48 घंटे का भूख हड़ताल अनशन शुरू हो गया है। यह अनशन 'सरिया जिला बनाव संघर्ष मोर्चा' के बैनर तले आयोजित किया गया है। इसमें मोर्चा के संयोजक त्रिभुवन मंडल के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए।

अनशन शुरू करने से पूर्व, संयोजक त्रिभुवन मंडल ने विवेकानंद चौक पर स्वामी विवेकानंद और शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद

सभी आंदोलनकारी शांतिपूर्वक अनशन स्थल पहुंचे और औपचारिक रूप से 48 घंटे के भूख हड़ताल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया लंबे समय से जिला बनने के लिए आवश्यक सभी अहर्ताओं को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि यहां अनुमंडल मुख्यालय, बेहतर रेल और सड़क संपर्क, उच्च शिक्षण संस्थान, बैंक, न्यायालय, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय सहित एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा पहले से मौजूद है। इसके बावजूद सरिया को अब तक जिला का दर्जा नहीं मिला है, जिससे क्षेत्र की जनता में उपेक्षा का भाव है। त्रिभुवन मंडल ने स्पष्ट किया कि संघर्ष मोर्चा अपनी मांग को पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचा रहा है।

सरकार ने जेपीएससी से कहा: विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अभी नहीं करें नियुक्ति

रांची। ब्रेक की वजह- शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन, रोस्टर क्लियरेंस का काम बाकी झारखंड के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं होगी। सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से कहा है कि अभी यूनिवर्सिटी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी।

क्योंकि क्लस्टर सिस्टम के अनुसार शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिसका रोस्टर क्लियरेंस की कार्यवाही चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है। डायरेक्टर सुधीर बाड़ा ने कहा है कि विवि और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा जाए। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में पुरानी संरचना के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती है।

पहले 5173, अब हो गए 6524 पद, 1351 बढ़े पुनर्गठन से पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कु 5173 स्वीकृत पद थे। पुनर्गठन के बाद इनमें 1351 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। अब शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 6524 हो गई है। हालांकि इन पदों पर नियुक्ति से पहले आरक्षण नियमों के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस अनिवार्य है और यही प्रक्रिया चल रही है। जेपीएससी को केवल नियुक्ति रोकने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

पुनर्गठन की जरूरत क्यों विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों और विद्यार्थियों की मांग में बदलाव आया है। नई शिक्षा नीति व बदलते कोर्स से कई नए विषयों की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आधार पर नए विषयों में पद सृजित किए गए हैं। जबकि कुछ पारंपरिक विषयों के पदों को डिमांड वाले विषयों में शिफ्ट किया गया है।

क्या पड़ेगा असर...राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है। कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है।

सोडूको प्रश्न (उत्तर अगले अंक में प्रकाशित होगा)

	3			8				1
		7	4		1		5	
9				5		2		
		2			5		1	
3			2	1		5		
5	9			6				2
		6	5		2			
		9	6				2	7
					8		6	5

पिछले अंक का उत्तर

1	3	2	5	6	7	9	4	8
5	4	6	3	8	9	2	1	7
9	7	8	2	4	1	6	3	5
2	6	4	9	1	8	7	5	3
7	1	5	6	3	2	8	9	4
3	8	9	4	7	5	1	2	6
8	5	7	1	2	3	4	6	9
6	9	1	7	5	4	3	8	2
4	2	3	8	9	6	5	7	1

चौखट पर हमारी
तुम्हारी
आने की आहट के
इशारे पास आए हैं।
मुश्किलों के बाद
आये सही वो
मंज़र और नज़ारे पास
आए हैं।।
खयालों से नहीं जाते
निकाले चर्चे समायत
के,
कि गिरते संभलते हम
खुद ही खुद में हारे पास
आए हैं।।

ग्राफ्टेड टमाटर-बैंगन की खेती ने बदली किस्मत:70 हजार रुपए हर माह हो रही आमदनी

गिरिडीह। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड निवासी दीपक कुमार एमसीए की पढ़ाई के साथ आधुनिक खेती में मिसाल बन गए हैं। वो अपनी चार एकड़ बंजर जमीन पर ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन उगाकर हर महीने 70 हजार रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं।

उनकी यह सफलता क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। दीपक ने अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग कर इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई है, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ फसल का उत्पादन और गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। दीपक ने बताया कि एमसीए की पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में कुछ दिनों तक जॉब किया पर खुद के कारोबार की ललक ने उन्हें गांव वापस आने का आइडिया दिया। गांव में अपनी जमीन पर उन्होंने खेती शुरू की और आज वो सफल किसान बन गए हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू: 125 भारतीय खिलाड़ी 8 खेलों में उतरेंगे; 1,168 मेडल्स के लिए 3,000+ एथलीट्स में होगा मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दांव पर होंगे।

कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। पहले एडिशन में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े 11 देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग जैसे खेल शामिल थे।

1930 से 1950 तक इस टूर्नामेंट को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। 1970 में यह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स बना और 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन हर चार साल में होता है। इसका मकसद कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों को बड़े इंटरनेशनल मंच पर कम्पटीशन का अवसर देना है। भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था।

इस बार कुल 10 खेलों में 215 मेडल इवेंट्स होंगे। इनमें 47 पैरा-स्पोर्ट्स मेडल इवेंट्स शामिल हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश जैसे खेल ग्लासगो 2026 का हिस्सा नहीं हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में ही जीते हैं।

भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया था।भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर बाकी सभी एडिशन में हिस्सा लिया है।

लंदन 1934 गेम्स में भारत की ओर से छह एथलीटों ने हिस्सा लिया था। भारतीय दल ने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया। इसी एडिशन में भारत ने अपना पहला मेडल जीता था। पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल हासिल किया था।

1934 में डेब्यू के बाद से भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 564 मेडल जीते हैं। इनमें 203 गोल्ड, 189 सिल्वर और 172 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

कॉमनवेल्थ माइल की वापसी: एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ माइल की वापसी होगी। यह इवेंट आखिरी बार 1966 में हुआ था। यानी करीब 60 साल बाद इसकी वापसी हो रही है। 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 1500 मीटर की जगह 1 मील यानी 1.609 किलोमीटर की रेस कराई जाएगी। इस बार मेंस के साथ विमेंस की माइल रेस भी होगी।

सबसे बड़ा पैरा-स्पोर्ट प्रोग्राम: 2026 में छह खेलों में पैरा-स्पोर्ट्स को पूरी तरह शामिल किया गया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा पैरा-स्पोर्ट प्रोग्राम है।

कितने वेन्यू पर होंगे इवेंट्स

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लासगो के चार अलग-अलग वेन्यू पर किया जाएगा। ग्लासगो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2014 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था।

ओपनिंग सेरेमनी में चानू-लवलीना फ्लैग बियरर होंगी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई 2026 को होगी। समारोह ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो एरीना में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। भारत की ओर से मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन फ्लैग बियरर होंगी। इसमें मशहूर ब्रिटिश सिंगर टॉम वॉकर परफॉर्म करेंगे।

बिजनेस न्यूज

सेंसेक्स 300 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 23,900 के नीचे; आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली हावी

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 23 जुलाई को लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक टूटकर 76,400 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि निफ्टी करीब 100 अंक फिसलकर 23,9003 के आसपास पहुंच गया। बाजार में सबसे अधिक दबाव आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों पर रहा, जिससे निवेशकों की धारणा कमजोर बनी रही।

इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 96 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.45 प्रतिशत, जापान का निक्केई 0.47 प्रतिशत और 3हांगकांग का हैंगसेंग1.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, अमेरिकी बाजारों में मंगलवार को हल्की गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोंस मामूली 6 अंक फिसला, जबकि नैस्डैक146 अंक और 3एसएंडपी 500 10 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुए।

विदेशी और घरेलू निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले सात दिनों में डीआईआई ने 1,255 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है, जबकि एफआईआई ने 667 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। ताजा कारोबारी सत्र में भी डीआईआई ने 418 करोड़ और एफआईआई ने 819 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

गौरतलब है कि 22 जुलाई को भी बाजार भारी दबाव में बंद हुआ था। उस दिन सेंसेक्स 715 अंक टूटकर 76,755 और निफ्टी 191 अंक गिरकर 23,996 पर बंद हुआ था। लगातार दूसरे दिन आई गिरावट से निवेशक सतर्क हैं और अब उनकी नजर वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतों तथा विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बनी हुई है।

सोना 274 बढ़कर 1.46 लाख पर पहुंचा:4 दिन में 4,398 महंगा हो चुका, चांदी आज 360 चढ़कर 2.26 लाख पर पहुंची

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 23 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 360 रुपए बढ़कर 2.26 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 274 रुपए चढ़कर 1.46 लाख रुपए पर पहुंच गया है। 4 दिन में सोना 4,398 रुपए और 10,346 रुपए चांदी महंगी हो चुकी है।

सोना इस साल ?13 हजार महंगा हुआ

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 12 हजार रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10द्द सोना 1.33 लाख रुपए के ऊपर था, जो अब 1.46 लाख रुपए पर पहुंच गया है।

वहीं, चांदी की कीमत में 4 हजार रुपए की गिरावट है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.26 लाख रुपए पर है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।

सोने-चांदी के दाम में आगे तेजी देखने को मिल सकती है: कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक सोने-चांदी के दाम अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं, हालांकि इनमें एकमुश्त निवेश करने से बचना चाहिए। अजय केडिया के अनुसार साल के आखिर तक सोना एक बार फिर 1.60 लाख और चांदी 2.80 लाख रुपए तक जा सकती है।

सऊदी अरब ज़मीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाएगा अनोखा स्टेडियम, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारी अभी से शुरू

भारत। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब खेलों का हब बन गया है, लेकिन सऊदी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल होगी, जब वहाँ 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। 8 साल बाद होने वाले फुटबॉल के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए सऊदी अरब ने अभी से खास तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब दुनिया का सबसे अनोखा स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहा है। खास बात ये है कि यह स्टेडियम ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा।

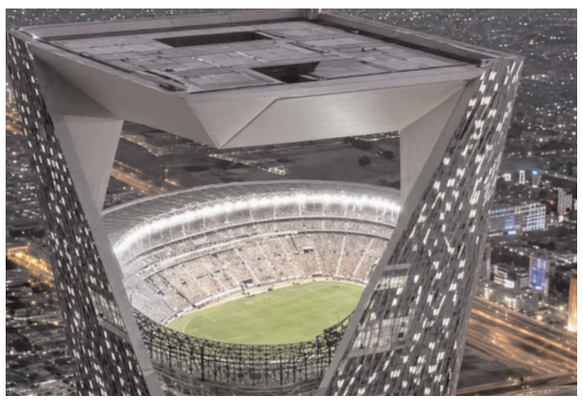

सऊदी के इस अनोखे स्टेडियम का नाम नियोम स्काई स्टेडियम होगा। यह नियोम परियोजना का हिस्सा होगा। नियोम, सऊदी अरब विज़न 2030 योजना के तहत डेवलप किया जा रहा दुनिया की सबसे महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस पूरे आधुनिक शहर को बनाने में करीब 500 बिलियन डॉलर खर्च होंगे।। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में सऊदी के प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने की थी। इसका उद्देश्य तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को तकनीक, पर्यटन और हरित ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। नियोम स्काई स्टेडियम भी इसी स्मार्ट सिटी में होगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार नियोम स्काई स्टेडियम को बनाने में करीब 1 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। इस स्टेडियम में दर्शक क्षमता 46,000 होगी। इस स्टेडियम में फीफा विश्व कप के ग्रुप मैच और क्वार्टरफाइनल कराए जाने की संभावना है।

खिलाड़ी और दर्शक इस स्टेडियम तक हाई-स्पीड ट्रांजिट सिस्टम और हाई-स्पीड लिफ्ट के ज़रिए पहुंचेंगे। रेगिस्तान की गर्मी से निपटने के लिए इस स्टेडियम में आधुनिक कूलिंग और क्लाइमेट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

नियोम स्काई स्टेडियम को चलाने के लिए आवश्यक बिजली जीवाश्म ईंधन से नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेडियम की बिजली का बड़ा हिस्सा विशाल सोलर प्लांट्स से आएगा। सऊदी के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध तेज़ हवाओं का इस्तेमाल विंड टर्बाइनों के ज़रिए इस स्टेडियम के लिए किया जाएगा। स्टेडियम में एलइडी लाइटिंग, स्मार्ट एयर कंडीशनिंग, प्राकृतिक रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और पानी बचाने वाली तकनीकों को भी अपनाया जाएगा।

श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई, मात्र 155 पर चार विकेट गवाए, भारतीय अंडर-19 टीम जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर

भारत की अंडर-19 टीम श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर है। भारतीय टीम को मुकाबले के अंतिम दिन सिर्फ 6 विकेट की दरकार है। जीत के लिए 472 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 4 विकेट गंवाकर सिर्फ 155 रन बनाए हैं। भारत के पास फिलहाल 317 रन की बढ़त है।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 411 रन बनाए। मेहमान खेमे से मनल चौहान ने 21 बाउंड्री के साथ 150 रन बनाए, जबकि कुशाग्र ओझा ने 111 रन की पारी खेली। इनके अलावा, यशबर्धन चौहान ने 78 रन का योगदान दिया। श्रीलंकाई खेमे से गिमहान मेंडिस ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई। इस पारी में दुलनिथ सिगेरा ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि सेथमिका सेनेविरात्ने ने नाबाद 25 रन जोड़े। भारत की तरफ से प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकटा, जगन्नाथ हेमचुदेशन और रोहित यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। मेहमान टीम के पास पहली पारी के आधार पर 263 रन की विशाल बढ़त थी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 208/3 के स्कोर पर घोषित करते हुए श्रीलंका के खिलाफ जीत के लिए विशाल टारगेट रखा। भारतीय खेमे से लक्ष्य राजेश ने 10 बाउंड्री के साथ 100 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि मनल चौहान ने 51 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई टीम की तरफ से कविजा कविजा गमागे ने 2 विकेट हासिल किए।

ओलिंपिक और खेल संघों की इंटरनल रिपोर्ट- भारत 28 साल में सबसे कमजोर प्रदर्शन कर सकता है

स्पोर्ट्स डेस्क। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सामने 28 साल में अपने सबसे कमजोर प्रदर्शन का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय ओलिंपिक संघ और अलग-अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को पैरा स्पोर्ट्स सहित 13 खेलों में 32 पदक मिलने का अनुमान है, जिसमें सिर्फ 7 गोल्ड शामिल हैं।

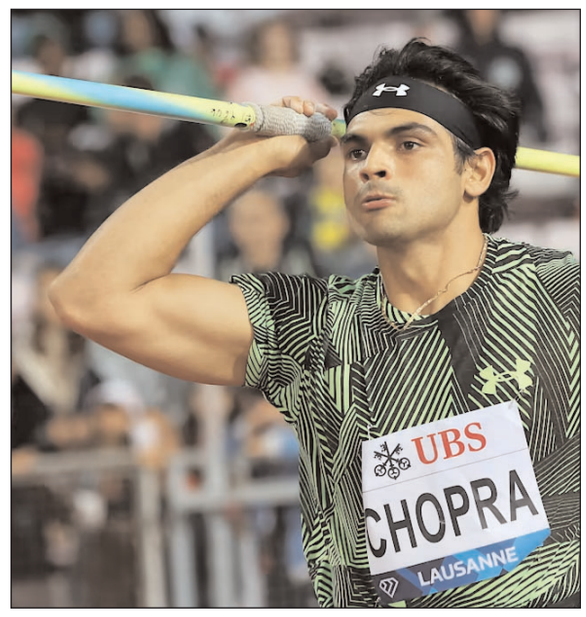

रिपोर्ट में नीरज चोपड़ा को भी गोल्ड का दावेदार नहीं माना गया है। नीरज ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वे ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। जिन सात खिलाड़ियों को गोल्ड का दावेदार माना गया है उनके नाम आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं।

2002 से हर बार भारत ने जीते 15 या ज्यादा गोल्ड

भारत के मेडल्स कम क्यों आएंगे?

1. जिन खेलों से सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, वही इस बार बाहर

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सफलता का आधार शूटिंग, कुश्ती और बैडमिंटन जैसे खेल रहे हैं। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार पदक जीते हैं। ग्लासगो 2026 के कार्यक्रम में इन तीनों खेलों को शामिल नहीं किया गया है। यही भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है।

ग्लासगो 2026 में बर्मिंघम 2022 के 19 की तुलना में सिर्फ 10 खेल होंगे। भारत के कई मेडल स्पोर्ट्स शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश और क्रिकेट इस बार शामिल नहीं हैं। बर्मिंघम में भारत के 61 में से 30 मेडल इन्हीं खेलों से आए थे। यही वजह है कि इस बार भारत का प्रदर्शन केवल खिलाड़ियों की फॉर्म पर नहीं, बल्कि गेम्स के स्पोर्ट्स प्रोग्राम पर भी निर्भर करेगा।

कामधेनू

वास्तु शास्त्र में, कामधेनु को शक्ति व ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक प्रतीक या वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। यहां वास्तु शास्त्र में कामधेनु का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ तरीके हैं :-

1. स्थान : अपने घर या कार्यालय के उत्तर-पूर्व दिशा में कामधेनु की मूर्ति या चित्र रखें। यह मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का आमंत्रण होता है और इससे सौभाग्य और अनुकूलता बढ़ती है।

2. पूजा कक्ष : अपने पूजा कक्ष में एक छोटी सी कामधेनु मूर्ति या चित्र रखें। मान्यता है कि इससे धार्मिक रीति व पूजा के दौरान आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा आती है।

3. धन कोण : यदि आप वास्तु शास्त्र में धन कोण की संकल्पना का पालन करते हैं, तो अपने धन कोण के नजदीक कामधेनु रखने से वित्तीय समृद्धि और सौभाग्य आकर्षित हो सकते हैं।

4. उपहार : कामधेनु घर की गृहप्रवेश या किसी नए व्यापार की शुरुआत में एक आदर्श उपहार हो सकती है।

ध्यान दें, वास्तु शास्त्र एक कई सिद्धांतों का समन्वय है, और कामधेनु उनमें से केवल एक तत्व है। अपनी विशेष आवश्यकताओं और स्थान के आधार पर वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श करना बेहतर होगा।

Vastu Guruji
www.vastuguruji.com
RAJ BHAWAN ROAD, CIVIL LINES, RAIPUR (C.G.) 492001

कॉमनवेल्थ गेम्स- भारतीय बॉक्सिंग टीम का सामान आयरलैंड में छूटा: बेलफास्ट से ग्लासगो जाते वक्त एयरपोर्ट पर रह गया; ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस-किट भी नहीं पहुंची

कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मंगलवार को बेलफास्ट से ग्लासगो पहुंची टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। टीम का आधा सामान बेलफास्ट में ही छूट गया, जहां खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। इनमें बॉक्सिंग गियर, किट और ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस शामिल हैं।

समाचार एजेंसी क्क्षड्ढ के अनुसार, टीम के सदस्यों ने बताया कि आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट से ग्लासगो जाने वाला विमान काफी छोटा था। इस वजह से काफी सामान वहीं छोड़ना पड़ा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी। बॉक्सिंग के मुकाबले 24 जुलाई से शुरू होने हैं। भारत ने गेम्स में 22 बॉक्स उतारे हैं। ये सभी खिलाड़ी 12 जुलाई से बेलफास्ट में स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे।

वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया (57 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा), परवीन हुड्डा (65 किग्रा), जादुमनी सिंह (55 किग्रा) और कपिल पोखारिया (90 किग्रा) का सामान मिसिंग है। प्लेयर्स के अलावा, मेंस टीम के हेड कोच सी. कुटप्पा का बैग भी ग्लासगो नहीं पहुंचा है। इसी महीने जब टीम दोहा से बेलफास्ट जा रही थी, तब भी लगेज को लेकर ऐसी ही समस्या आई थी।

महिला कोच को अलग होटल में ठहराया, तैयारियों पर असर

सामान छूटने के साथ-साथ टीम को रुकने की व्यवस्था में भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। महिला मुक्केबाजों की कोच को उस होटल में कमरा नहीं मिला है, जहां खिलाड़ी ठहरी हुई हैं। कोच को खिलाड़ियों से दूर दूसरे होटल में रखा गया है, जिससे टूर्नामेंट की तैयारियों और टीम के तालमेल में परेशानी आ रही है।

राजीव भवन घेराव के दौरान भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने वॉटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल

रायपुर। राजधानी रायपुर में बुधवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब भाजपा ने शंकर नगर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव किया। यह प्रदर्शन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।

भाजपा का यह प्रदर्शन नई दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी जैसे ही राजीव भवन की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तभी सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए।

कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। दोनों ओर से लकड़ी के टुकड़े, पानी के पाउच और चप्पलें फेंकी गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने पहले दोनों पक्षों को पीछे हटाने का प्रयास किया, लेकिन तनाव बढ़ने पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।

पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात धीरे-धीरे नियंत्रण में आए और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को मौके से हटाया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान शंकर नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में होने की बात कही।

सरगुजा की आर्द्रभूमि में फिर दिखा राष्ट्रीय गौरव पक्षी सारस क्रेन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की आर्द्रभूमियों में राष्ट्रीय गौरव पक्षी और दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी 'सारस क्रेन' का दिखना पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद सुखद खबर है। छत्तीसगढ़ में इन पक्षियों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए इनका किसी स्थानीय जलाशय या वेटलैंड में दिखाई देना एक महत्वपूर्ण घटना है। पक्षी 'सारस क्रेन' जीवनभर के लिए अपना एक ही साथी चुनते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें प्रेम और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि और पक्षी जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सरगुजा जिले से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सरगुजा वनमंडल के लखनपुर परिक्षेत्र स्थित कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के एक जोड़े का सफलतापूर्वक अवलोकन किया गया है। यह महत्वपूर्ण अवलोकन वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत के मार्गदर्शन में चल रही नियमित निगरानी के दौरान दर्ज किया गया। क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग तकनीकी सहायक श्री धनीराम और बीट गार्ड श्री राजेंद्र खुजूर द्वारा की जा रही है। उनके प्रयासों से सारस क्रेन के जोड़े की यह महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा सकी। सारस क्रेन भारत के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक है और विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। किसी आर्द्रभूमि में इसकी उपस्थिति उस क्षेत्र के स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारस क्रेन के प्रमाणित और नियमित अवलोकन वर्तमान में सरगुजा क्षेत्र से ही प्राप्त हो रहे हैं।

मल्हार में खुली छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा

रायपुर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी मल्हार के लिए बुधवार का दिन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। यहां छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की 629वीं शाखा तथा बिलासपुर जिले की 37वीं शाखा का शुभारंभ किया गया। नई शाखा खुलने से अब मल्हार और आसपास के गांवों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूसरे शहरों या कस्बों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

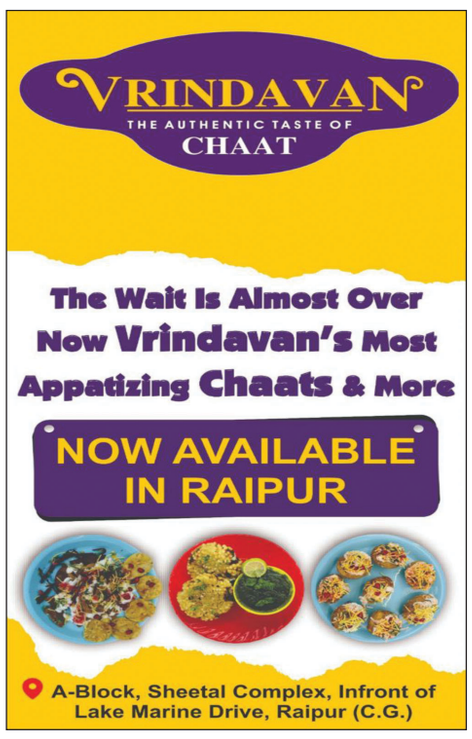

स्मार्ट मीटर से बिजली बिल हुआ आसान, मोर बिजली मोबाइल ऐप से घर बैठे मिल रही हर पल की जानकारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर परियोजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत रायगढ़ जिले में 01 लाख 13 हजार 705 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। रायगढ़ जिले के उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली बिल को लेकर पहले जैसी असमंजस की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि बिजली खपत से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। बिजली का उपयोग भी सोच-समझकर करते है। जिससे बिजली खपत पर नियंत्रण हो रहा है। वहीं ऑनलाइन बिल भुगतान से समय की बचत हो रही है और रियल टाइम जानकारी से पारदर्शिता बढ़ी है।

मोर बिजली ऐप से हर पल की जानकारी

रायगढ़ निवासी रिकेश कुमार सोनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल पूरी तरह पारदर्शी हो गया है। अब मीटर रीडिंग के लिए किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मोर बिजली ऐप के माध्यम से प्रतिदिन यह देखा जा सकता है कि कितनी बिजली खर्च हुई, अनुमानित बिल कितना बनेगा और भुगतान कब करना है। इससे बिल संबंधी परेशानियां लगभग समाप्त हो गई हैं।

बिजली खपत पर रखना हुआ आसान नियंत्रण

उपभोक्ता मोहन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर बिजली विभाग से संपर्क किया और अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब वे अपनी बिजली खपत पर लगातार नजर रख पाते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक - **करण सिंह होरा** द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. जयस्तंभ चौक रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) से मुद्रित कर लक्ष्मी निवास नल घर चौक, अहमद जी भाई कालोनी रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन-492001 से प्रकाशित. **संपादक- करन सिंह होरा** मो. - 9669000000 CHHBIL/2023/88684